जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 वर्षः 49 संख्याः 335 प्रभात कोटा, मंगलवार 17 सितम्बर, 2024 कोटा/24/2012-14 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

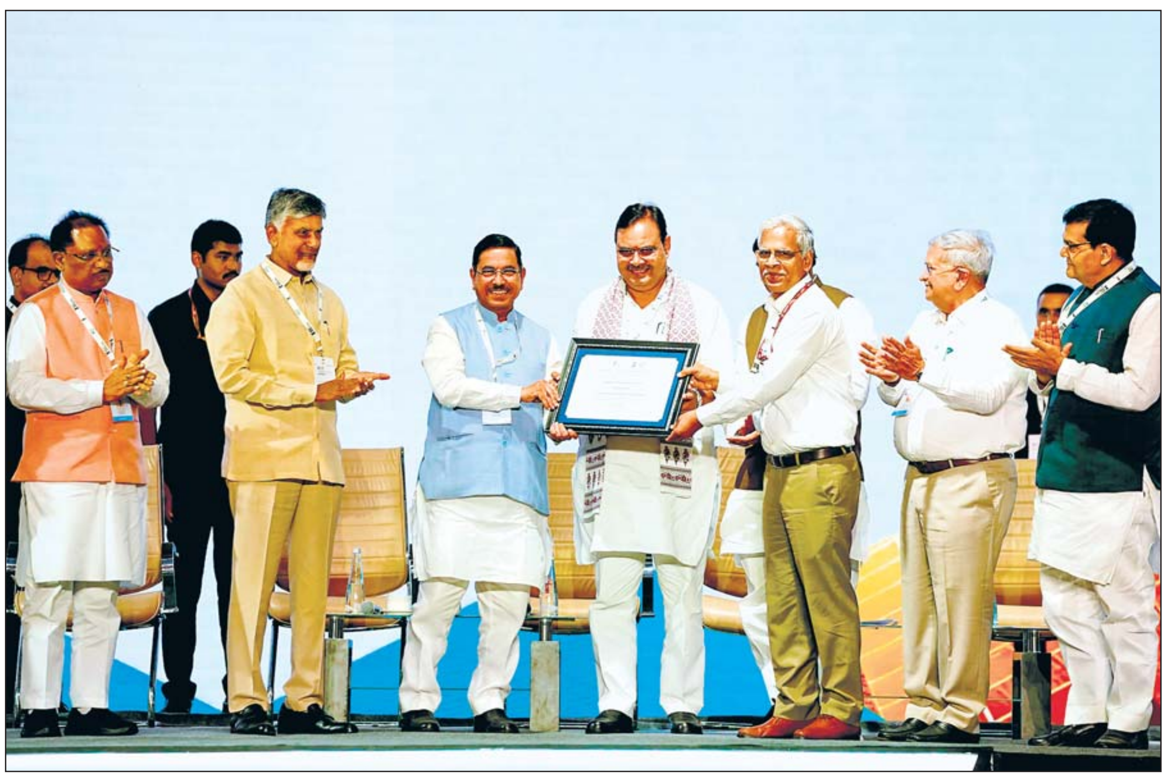

गुजरात के गांधी नगर में आयोजित चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वैस्टर्स मीट में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल को अवॉर्ड प्रदान किया गया। रिन्युएबल एनर्जी के कुल उत्पादन में राजस्थान को देश भर में दूसरा स्थान मिला है।

राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश भर में पहले स्थान पर

गुजरात के गांधी नगर में आयोजित चौथे ग्लोबल रिन्युएबल एनर्जी इन्वैस्टर्स मीट में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल को अवॉर्ड प्रदान किया गया

- **रिन्युएबल एनर्जी के कुल उत्पादन में राजस्थान को देश भर में दूसरा स्थान मिला है।**
- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राजस्थान का भड़ला सोलर पार्क 2,245 मेगावाट क्षमता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है और हमारी सरकार रिन्युएबल एनर्जी में उत्पादन बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है।**
- **कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया, जिसमें गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा के मुख्यमंत्री व केन्द्रीय रिन्युएबल एनर्जी मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद थे।**

जयपुर, 16 सितम्बर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऊर्जा निवेश बैठक और एक्सपो (री-इन्वेस्ट 2024) का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उपस्थित रहे।

गैर–जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 200 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए राजस्थान को समारोह में सम्मानित किया गया। राज्य ने कुल सोलर ऊर्जा क्षमता श्रेणी में सर्वोच्च उपलब्धि हासिल करते हुए देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की श्रेणी में राजस्थान द्वितीय स्थान पर रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर ने केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के हाथों से यह पुरस्कार ग्रहण किए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज राजस्थान भारत में अक्षय ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर है। यहां का भड़ला सोलर पार्क 2 हजार 245 मेगावाट स्थापित सोलर क्षमता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेशकों के लिए प्रदेश में अनुकूल वातावरण उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य में 28 गीगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं से लगभग 470 करोड़ यूनिट बिजली उत्पादित हो रही है और 32 गीगावाट की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। साथ ही, राज्य में 142 गीगावाट सौर ऊर्जा और 284 गीगावाट पवन ऊर्जा के उत्पादन की संभावनाएं हैं। हम वर्ष 2031-32 तक 115 गीगावाट सौर एवं पवन ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं।

शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार बिजली क्षेत्र में सुधारों के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हमने "विकसित राजस्थान 2047" के संकल्प को पूरा करने के लिए अगले 10 वर्षों में बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए कार्ययोजना तैयार कर ली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान के सभी जिलों में आदर्श सौर ग्राम विकसित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि वैश्विक सहयोग, तकनीक, अनुसंधान, प्रशिक्षण और निवेश की सहायता से प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। इस दिशा में राज्य सरकार 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में "राइज़िंग राजस्थान" इन्वेस्टमैंट समिट का आयोजन करने जा रही है, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में निवेश आएगा। उन्होंने बताया कि राजस्थान में विगत 9 महीनों में बिजली तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ 1 लाख 64 हजार करोड़ रुपये के एम.ओ.यू. किए हैं। साथ ही, केन्द्र सरकार ने राज्य में 5 हजार 292 मेगावाट क्षमता के तीन अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क भी स्वीकृत किए हैं।

कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी, केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपद येस्सो नाइक सहित विभिन्न देशों एवं राज्यों के प्रतिनिधिगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

ममता बनर्जी आंदोलनकारी डॉक्टरों से दिन में पांच बार मिलीं

मु.मंत्री पूर्णतया प्रयासरत हैं, डॉक्टर अपना आंदोलन वापस ले लें

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- **बंगाल की आँखें अब सुप्रीम कोर्ट पर फोकस्ड हैं, जहाँ, आज, 17 सितम्बर को डॉक्टरों के आंदोलन व जूनियर डॉक्टर ने "रेप" व हत्या के मामले की सुनवायी होगी।**
- **डॉक्टरों ने अपना वकील भी बदल दिया है। अब जानी-मानी अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह आंदोलनकारी डॉक्टरों का पक्ष रखेंगी। पहले, डॉक्टरों की वकील गीता लूथरा थीं, जो सरकार के वकील कपिल सिब्बल की तुलना में काफी जूनियर थीं।**
- **बहरहाल, सी.बी.आई. ने उस थाने के ऑफिसर इंजार्च व दो कनिष्ठ पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया है।**
- **जनता को डर है कि छोटे-मोटे पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी करके खानापूर्ति न हो जाये और असली गुनहगार, उच्चाधिकारी, चुपचाप "निर्दोष" निकल न जायें।**

नई दिल्ली, 16 सितम्बर। एक प्रशिशु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले से निपटने के राज्य सरकार के तरीके के खिलाफ बंगाल एक सामूहिक व संयुक्त विरोध का सामना कर रहा है।

बंगाल एक तरह की सामाजिक क्रांति के दौर से गुजर रहा है। कुछ युवाओं, मैडिकल छात्रों व ट्रेनी डॉक्टर्स का यह आंदोलन पूरे राज्य का ध्यान खींच रहा है।

ट्रेनी डॉक्टर का दुष्कर्म और हत्या अस्पताल परिसर में हुई तथा उस लड़की के साथ हुए जघन्य अपराध के खिलाफ न्याय की मांग के लिए आंदोलन शुरु हुआ। राज्य भर के परिवार, जिनके घरों में बेटी हैं, इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। एक अस्सी वर्षीय महिला तो आंदोलनरत डॉक्टर्स को भोजन देने के लिए आई थी।

यह बात सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को परेशान कर रही है जो आंदोलनरत छात्रों से आंदोलन में पिछड़ रही है। तृणमूल इन पर बल प्रयोग भी नहीं कर सकती है, जैसा राजनैतिक दलों के उन कार्यकताओं के साथ किया था, जिन्होंने जघन्य हत्या के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की थी।

राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी डॉक्टर्स को आंदोलन वापस लेने के लिए मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। खबर लिखे जाने तक मुख्यमंत्री का जूनियर डॉक्टर्स के साथ वार्ता का पांचवां दौर चल रहा था।

अब सारे आंदोलन में एक नया कोण जुड़ गया है। सभी की नज़रें मंगलवार को आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैं।

राज्य सरकार पिछली बार दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दे रही है कि डॉक्टर्स को तुरंत काम पर लौट आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स को 10 सितम्बर शाम 5 बजे तक का समय दिया था काम पर लौटने के लिए।

अभी तक जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से गीता लूथरा सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रही थीं, उनका सामना कपिल सिब्बल से था। पर, 17 सितम्बर को जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से हाई प्रोफाइल वकील इंदिरा जयसिंह पेश होंगी। अब सभी की नज़रे इस सुनवाई पर हैं।

हाल ही में जब प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के घर गणेश पूजा के लिए गए थे तो इंदिरा जयसिंह ने इसकी कड़ी आलोचना की थी। जयसिंह ने शक्ति प्रदर्शन की हद पार करने के लिए सी.जे.आई. और प्रधानमंत्री दोनों की आलोचना की थी।

इसी बीच सी.बी.आई. ने हत्या के मामले की हैंडलिंग को लेकर ताला पार्क पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज (ओ.सी.) को गिरफ्तार कर लिया।

सी.बी.आई. ने इन शिकायतों पर ध्यान दिया है कि ओ.सी. अपराध की जगह पर देर से आए, उन्होंने जनरल डायरी में लिखा, प्रशिक्षु डॉक्टर जीवित थी। कई अन्य गड़बड़ियों को भी सी.बी.आई. ने नोट किया।

पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि ओ.सी. व अन्य निचले दर्जे के पुलिस

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एक बार फिर ट्रम्प को जान से मारने की कोशिश

- **सीक्रेट सर्विस के एजेन्ट्स ने एक संदिग्ध को राइफल समेत गिरफ्तार किया।**

नयी दिल्ली, 16 सितंबर। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले एक बार फिर पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को जान से मारने की कोशिश की गई है। रविवार को फ्लोरिडा में उनको जान से मारने का प्रयास किया गया जिसमें वो बाल–बाल बच गए। इस पूरे मामले में 58 वर्षीय एक संदिग्ध को सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने गिरफ्तार कर लिया है। एफ.बी.आई. के मुताबिक घटनास्थल से एक एके-47 शैली की राइफल भी बरामद की गई है, जिसमें एक स्कोप और एक गो प्रो कैमरा लगा हुआ था। कुछ सप्ताह पहले भी ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ था। पेनसिल्वेनिया में हुए हमले के दौरान संदिग्ध को मौके पर ही मार गिराया गया था। इस दौरान गोली ट्रंप के कान को छूते हुए निकल गई थी।

ट्रंप पर हमले की कोशिश उस वक्त की गई जब वो गोल्फ खेल रहे थे। जब ट्रंप गोल्फ ग्राउंड पर थे तो वहां से कुछ दूरी पर छिपकर बैठे "अमेरिकी सीक्रेट

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तमिलनाडु के मु.मंत्री स्टालिन प्र.मंत्री मोदी से मिलने की कोशिश में जुटे

स्टालिन ज्यादा स्वायत्तता व संघवाद के संरक्षण के मुद्दे पर प्र.मंत्री से चर्चा करना चाहते हैं

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- **स्टालिन जो प्रमुख मुद्दे उठाएंगे, उसमें प्रमुख है नैशनल एजुकेशन पॉलिसी। स्टालिन का कहना है कि मौजूदा शिक्षा नीति तमिल भाषा व संस्कृति के लिए खतरा है।**
- **स्टालिन मैट्रो प्रोजैक्ट के लिए केन्द्र से सहायता की गुजारिश भी करेंगे। राज्य सरकार इस प्रोजैक्ट पर 18,000 करोड़ रूपए खर्च कर चुकी है। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य सरकार के दावे का खंडन किया व कहा कि केन्द्र ने 21,000 करोड़ रूपए दिए थे, पर, राज्य सरकार सिर्फ 5,880 करोड़ रूपए ही खर्च कर पाई है।**

नई दिल्ली, 16 सितम्बर। अनदेखे रह कर काम करने वाले और तथाकथित राष्ट्रीय मीडिया के राडार मे नीचे उड़ान भरते रहने वाले, तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री एम.के.स्टालिन चुपचाप किन्तु उस समय दृढ़तापूर्वक संघवाद को प्रचारित–प्रसारित जरूर करते हैं, जब राज्य सरकारों के अधिकार–क्षेत्र की बात आती है। इस बात की प्रबल संभावना है कि वे जल्दी ही प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी से मिलेंगे तथा राज्यों को और अधिक स्वायत्तता देने के लिये उन पर दबाव डालेंगे। प्रधानमंत्री के साथ सम्भावित मीटिंग में, वे इस बात के लिए भी दबाव डाल सकते हैं कि राज्यों को शिक्षा तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण सम्बन्धी गतिविधियों के बारे में और अधिक अधिकार दिए जायें।

स्टालिन प्रधानमंत्री के साथ जल्दी से जल्दी मीटिंग करने की कोशिश मे बताये जाते हैं, ताकि वे उनके साथ दो प्रमुख नीतिगत मुद्दों पर चर्चा कर सकें। पहला मुद्दा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे लेकर राज्य को आपत्ति है, क्योंकि तमिलनाडु को आशंका है कि इससे शिक्षा के मामले में राज्य की स्वायत्तता खतरे में पड़ जायेगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (एन.ई.पी.) में समान शैक्षिक ढ़ाँचे को लाया गया है, जिसे लेकर कई राज्य, खासतौर से तमिलनाडु, यह महसूस कर रहे हैं कि एन.ई.पी. उनकी क्षेत्रीय पहचान तथा भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता की जड़े काटेगी। दरअसल, केन्द्र ने त्रिभाषा सूत्र – हिन्दी, अंग्रेजी तथा राज्य की स्थानीय भाषा– पर जोर दिया है। लेकिन तमिलनाडु ने स्कूलों में दो भाषा व्यवस्था – अंग्रेजी और तमिल को अपना रखा है। यही व्यवस्था पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक सरकार के शासनकाल में थीं इस तथ्य से यह बात

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजू ठेहट हत्याकांड में नाबालिग को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी

- **सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश करने की हिदायत दी और कहा कि बोर्ड का जमानत आदेश जारी करे।**

जयपुर, 16 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के चर्चित राजू ठेहट हत्याकांड के एक नाबालिग को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस ए.एस. ओका और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ ने यह आदेश नाबालिग की आपराधिक याचिका को स्वीकार करते हुए दिए। अदालत ने कहा अपीलार्थी नाबालिग को तत्काल किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाए और बोर्ड जमानत आदेश जारी करे।

अपील में अधिवक्ता अभिसार भानू सिंह ने अदालत को बताया कि मामले में अपीलार्थी से किसी तरह की बरामदगी नहीं हुई है। इसके अलावा प्रकरण में आरोप पत्र भी पेश हो चुका है। उस पर आरोप है कि वह हत्याकांड में शामिल आरोपियों को मोबाइल, वाहन और हथियार उपलब्ध कराने से जुड़ा था। जबकि इस बात को कोई साक्ष्य अभियोजन पक्ष के पास नहीं है। केवल कॉल रिकॉर्ड के आधार पर अपीलार्थी को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कर्नाटक में कई अभिनेत्रियों ने यौन शोषण की शिकायत की

फिल्म उद्योग ने कर्नाटक सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- **कन्नड़ फिल्म उद्योग के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश सरकार से मुलाकात की और एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की मांग की, जो फिल्म उद्योग में महिला सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए दिशा निर्देश देगी।**
- **इससे पहले मलयालम फिल्म उद्योग में हेमा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद यौन शोषण की घटनाओं की रोकथाम के लिए कमेटी बनाने की मांग उठी थी और तमिलनाडु से भी ऐसी ही बातें सामने आ रही हैं।**

नई दिल्ली, 16 सितम्बर। कर्नाटक फिल्म उद्योग ने भी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक ऐसी कमेटी गठित करने की माँग की है, जो इस उद्योग के कामकाज की मॉनिटरिंग करे तथा महिला कलाकारों के लिये कार्य करने का एक अच्छा एवं विवेकपूर्ण माहौल पैदा करने के लिये सख्त कार्यवाही कर सके। वस्तुत: शीर्ष अभिनेताओं और अभिनेत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य के मुख्यमंत्री एस. सिद्धारमैया से मिला और उनके समक्ष अपनी यह माँग रखी कि उच्च या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाये, जो यौन–उत्पीड़न की शिकायतों की जाँच करे तथा ऐसे यौन–दुर्व्यवहार के केसों के खिलाफ की जाने वाली कार्यवाही की गाइडलाइन भी तैयार करे।

हालाँकि, सरकार ने अभी ऐसा कोई वादा नहीं किया है, लेकिन जब से हेमा आयोग की रिपोर्ट में मलयालम फिल्म उद्योग की स्थिति का विस्तृत ब्यौरा दिया है, तभी से इस मनोरंजन उद्योग में यौन–उत्पीड़न के खिलाफ स्वर मुखर होने लगे हैं।

बहुत सारी फिल्म अभिनेत्रियाँ फिल्म उद्योग में हुये अपने यौन–उत्पीड़न की कहानियाँ बताने के लिये अब आगे आने लगी हैं तथा तमिलनाडु में भी जानी–मानी अभिनेत्रियों ने भी अब इस संबंध में विधिवत शिकायतें दर्ज कराई हैं।

कर्नाटक फिल्म संगठन ने यह मांग भी की कि उक्त कमेटी तीन माह में रिपोर्ट व सुझाव दे। ज्यादा से ज्यादा अभिनेता–अभिनेत्रियाँ इण्डस्ट्री को स्वच्छ करने की माँग कर रहे है, इसलिए इस कमेटी को बनाए जाने का आग्रह जोर पकड़ रहा है।

हालाँकि, सरकार ने अभी इस पर कोई ठोस वादा नहीं किया है ना ही कोई निर्णय प्रक्रिया शुरु हुई है, पर सूत्रों ने बताया कि सरकार इस प्रार्थना पर विचार कर रही है और इसे स्वीकार कर सकते है। इस बैठक में कर्नाटक राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नागलक्ष्मी चौधरी भी मौजूद थी। सभी की मांग थी कि कार्य स्थल पर यौन शोषण रोकने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'मोदी सरकार ही कश्मीर में शांति ला सकती है'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- **केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किश्तवाड़ की जनसभा में दावा किया। ज्ञातव्य है कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों में सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन था।**

नई दिल्ली, 16 सितम्बर। गृहमंत्री अमित शाह का दावा है कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केवल भाजपा ही जम्मू–कश्मीर में शांति सुनिश्चित कर सकती है सोमवार को नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन जे.एण्ड के. के किश्तवाड में आयोजित एक जनसभा में आयोजित एक जनसभा में शाह ने यह दावा किया चुनाव प्रचार के अंतिम दिन उन्होंने जम्मू–कश्मीर में तीन जनसभाएं कीं। दो उन्होंने अन्य जनसभाएं गुलमर्ग के छतरगर्क स्टेडियम तथा रामबन विधानसभा क्षेत्र के चन्दरकोट कस्बे में सम्बोधित कीं।

कांग्रेस के इस दावे को खारिज करते हुए, कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के प्रथम 100 दिनों में कोई उन्नति नहीं हुई है, गृहमन्त्री अमित शाह ने कहा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)